

STATEMENT II

State Governments, Employers' and Workers' Organisations, who were represented at the 29th Session of the Standing Labour Committee (New Delhi —July 23-24, 1970)

State Governments and Union Territories

1. Andhra Pradesh
2. Assam
3. Bihar
4. Gujarat
5. Haryana
6. Jammu and Kashmir
7. Kerala
8. Madhya Pradesh
9. Maharashtra
10. Mysore
11. Orissa
12. Punjab
13. Rajasthan
14. Tamil Nadu
15. Uttar Pradesh
16. West Bengal
17. Delhi Administration
18. Goa, Daman, Diu
19. Himachal Pradesh
20. Pondicherry
21. Tripura

Employers' Organisations

1. The Employers' Federation of India.
2. All India Organisation of Employers.
3. The All-India Manufacturers' Organisation.

Workers' Organisations

1. Indian National Trade Union Congress.
2. Hind Mazdoor Sabha.

बरियारपुर डाकघर

696. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के मुंगेर जिले के जमानपुर क्षेत्र में बरियारपुर डाकघर में, जो वहां के 50,000 लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, कर्मचारियों की इतनी कमी है कि वहां डाक वितरित करने के लिये चपरासी भी नहीं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कार्यालय की इमारत बेकार हो चुकी है तथा वहां पर पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ग) क्या मुंगेर के डाक अधीक्षक को इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार इसके विकास के लिए एक नये भवन का निर्माण करने की अविलम्ब व्यवस्था करने का विचार रखती है तथा उक्त डाकघर में पेय जल की सुविधा प्रदान करने तथा वहां पर्याप्त कर्मचारी और पर्याप्त कार्यालय-सामग्री आदि की व्यवस्था करने हेतु कार्यवाही करने का भी विचार रखती है ?

BARIAITRUPUR POST OFFICE

696. SHRI I. P. YADAV: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that [here is so much shortage of staff in the post office at Bariarpur in the Jamalpur area of District Monghyr in Bihar which caters to the needs of 50,000 people that there is not even a peon to deliver the dak;

(b) whether it is also fact that its office building has become useless and that there is no arrangement of drinking water there;

(c) whether the Postal Superintendent, Monghyr has received representations in this connection and if so, the action taken thereon and if not, the reasons therefor; and

(d) whether Government propose to make immediate arrangement to construct a new building for its development and take steps to provide facilities of drinking water, adequate number of staff and sufficient office equipments etc. at the said post office?]

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) हाल ही में इस इमारत की पूर्ण रूप से मरम्मत की गई है। पेय जल के लिये ट्यूबवैल भी लगाया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) नई इमारत बनाने का कोई विचार नहीं है। फिर भी मौजूदा इमारत के विस्तार की योजना बनाई जा रही है। हाल ही में प्रवीण कार्यालय-सामग्री सप्लाई की गई है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (PROF. SHER SINGH):

(a) No.

(b) Thorough repairs to the building have been, carried out recently. One tube well for drinking water has been provided.

(c) No.

(d) There is no proposal for the construction of a new building. However plans for extension of the existing building are under preparation. Adequate office equipment has been supplied recently.]

ट्रैक्टरों की आवश्यकता

697. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू वर्ष में कुल कितने ट्रैक्टरों तथा पावर टिल्लरों की आवश्यकता होगी तथा सरकार द्वारा ऐसे कितने उपकरणों की पूर्ति किसानों को किये जाने की सम्भावना है तथा कब तक ऐसे उपकरणों की मांग पूर्ण रूपेण पूरी हो जायगी ;

(ख) देश भर में ऐसे उपकरणों की मरम्मत की सुविधाएं प्राप्त कराने के लिये सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है तथा कब तक किसानों को देशी ट्रैक्टर उपलब्ध कराने का विचार किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में ट्रैक्टरों के पुर्जे तथा टायर इत्यादि उपलब्ध नहीं होते हैं ; और

(घ) ट्रैक्टर तथा दूसरे प्रकार के कृषि उपकरणों का देश में ही निर्माण करने की योजना का ठीक-ठीक स्वरूप क्या है ?

REQUIREMENTS OF TRACTORS

697. SHRI J. P. YADAV: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the total number of tractors and power tillers required in the country during the current year and the number of such implements likely to be made available by Government to the farmers and when the demands of such implements is likely to be met in full;

(h) what steps are proposed to be taken to provide repairing facilities of such implements all over the country and by when it is proposed to make indigenous tractors available to the farmers;

(c) whether it is a fact that spare parts of tractors and tyres etc. are not available to the farmers in sufficient quantity; and

(d) what are the exact details of the plan for the indigenous manufacture of the tractors and other types of agriculture implements?]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सह-कारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथराव शिन्दे) : (क) वर्ष 1969-70 के लिये ट्रैक्टरों तथा पावर टिल्लर्स की मापेज मांग क्रमशः 1 14 लाख तथा 6,000 की है। इनकी पूर्ति के लिये 35,000 ट्रैक्टरों तथा 3,150 पावर टिल्लर्स की आपात करने का निश्चय किया गया। ट्रैक्टरों के देशीय उत्पादन तथा उनके आयात में वृद्धि के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है। किन्तु हाल ही के वर्षों में अच्छी फसल होने के कारण इनकी मांग में अत्यधिक वृद्धि होने से मांग की पूर्णतः पूर्ति नहीं की जा सकी है।

(ख) और (घ) राजकीय कृषि उद्योग निगमों नागालैण्ड तथा मेघालय को छोड़ कर समस्त राज्यों में स्थापित कर दिये गये हैं।